कनेक्टिविटी देने के लिए यूपी में बनेगा उत्तर-दक्षिण कारिडोर

मुख्यमंत्री योगी ने कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में उत्तर-दक्षिण कारिडोर का विकास जरूरी है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को उत्तर-दक्षिण कारिडोर के निर्माण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अधिकांश राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पूर्व-पश्चिम दिशा में केंद्रित हैं। आवश्यकता है कि नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी छोर बुंदेलखंड के जिलों को जोड़ने के लिए कारिडोर का निर्माण किया जाए।

मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर-दक्षिण कारिडोर के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत आने वाले हिस्सों में एनएचएआइ का सहयोग लिया जाए। शेष मार्गों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जाए। कारिडोर के लिए जहां जरूरी हो, वहां पर ग्रीनफील्ड रोड परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएं। यह कारिडोर न केवल उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश व झारखंड और आगे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से जोड़ेगा, बल्कि सीमावर्ती जिलों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री उत्तर प्रदेश की इकाइयों से ही ली जाएं। उन्होंने कहा कि जिन धार्मिक स्थलों पर प्रतिवर्ष पांच लाख तक श्रद्धालु आते हैं, उन धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे 272 मार्गों के अलावा औद्योगिक और लाजिस्टिक पार्कों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए 33 परियोजनाओं को भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रयागराज में गंगा नदी पर सलोरी से झूंसी को जोड़ने के लिए और नैनी पुल के समानांतर दो पुलों का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी में मालवीय सेतु के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित रेल व रोड ब्रिज, यातायात और कनेक्टिविटी की समस्या भी जल्द दूर होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ययोजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी जिलों व विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य बराबर हों। विकास में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न न हो। परियोजना को प्रारंभ करने से पहले उसकी उपयोगिता, संभावित प्रभाव और स्थानीय जनता पर उसके असर का अध्ययन जरूर किया जाए।

संबंधित खबर >> पेज 10

- निर्माण कार्यों में उत्तर प्रदेश में निर्मित सामग्री को लोक निर्माण विभाग देगा प्राथमिकता
- पुलों और रेल ओवरब्रिज की परियोजनाओं को निर्धारित समय में किया जाए पूरा

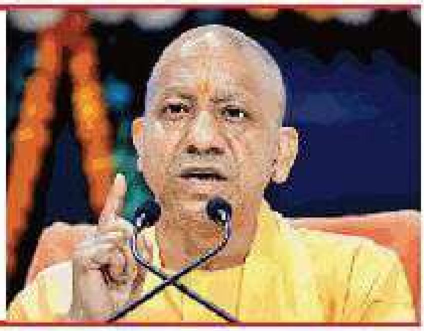

प्रस्तावित कारिडोर

लखीमपुर-लखनऊ-चित्रकूट-सतना	111 किमी	1425 करोड़
श्रावस्ती-गोंडा-अयोध्या-प्रयागराज-रीवा	337 किमी	3288 करोड़
भोगनीपुर-औरैया-कन्नौज-हरदोई-सीतापुर-लखीमपुर-गौरीफंटा (नेपाल सीमा)	342 किलोमीटर	3152 करोड़ रुपये
पीलीभीत-शाहजहांपुर-कानपुर-हमीरपुर-छतरपुर (मध्य प्रदेश)	469 किलोमीटर	3200.4 करोड़ रुपये
ककरहवा-बस्ती-आजमगढ़-जौनपुर	273 किमी	1050 करोड़
पडरौना-देवरिया-मऊ-सलेमपुर-मेदिनीनगर (झारखंड)	401 किलोमीटर	4007.4 करोड़ रुपये
नजीबाबाद-अमरोहा-इटावा-ललितपुर	640 किमी	7545 करोड़
मुरादाबाद-अलीगढ़-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान)	268 किलोमीटर	1584 करोड़ रुपये)

नोट: कारिडोर की कुछ सड़के पहले से बनी हुई हैं, कुछ पैच का निर्माण होगा।